

## अध्याय V: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

### 5.1 प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना

#### 5.1.1.1 प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (मंत्रालय) 'प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना' नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है। एटीआई योजना के मूल उद्देश्य पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और उद्यमों की स्थापना में उनकी सहायता करके नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास, उद्यमशीलता के आधार का विस्तार करने और ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से स्वदेशी उद्यमिता विकसित करना है। इस योजना के तहत सहायता के दो घटक हैं-पहला प्रशिक्षण कार्यक्रमों<sup>1</sup> के लिए धन उपलब्ध कराना और दूसरा पूंजीगत सहायता के लिए है।

#### 5.1.1.2 योजना का वित्तपोषण

2012-13 से 2019-20 के दौरान, मंत्रालय ने योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹358.99 करोड़ और पूंजीगत सहायता के लिए ₹62.25 करोड़ जारी किए। विवरण अनुलग्नक-XXXI में उल्लिखित हैं।

#### 5.1.1.3 लेखापरीक्षा का अभिगम, कार्यप्रणाली और कार्य क्षेत्र

दिसंबर 2016 में उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति और मंत्रालय के आदेश पर एटीआई योजना की लेखापरीक्षा योजना के उद्देश्यों की उपलब्धियों की जांच करने के लिए अप्रैल 2012 से मार्च 2020 (आठ वर्ष) की अवधि के लिए दो चरणों में शुरू की गई थी। 6 जुलाई 2018 को मंत्रालय के साथ एंटी कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसके बाद, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय में एटीआई योजना से संबंधित अभिलेखों और जुलाई 2018 से नवंबर 2018 के बीच पांच नमूना कार्यान्वयन संस्थानों की जांच की। रिपोर्ट का मसौदा 28 जून 2019 को

<sup>1</sup> उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपीज़), उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपीज़) और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीज़)

मंत्रालय को जारी किया गया था और 8 नवंबर 2019 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेखापरीक्षा में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से पाया गया कि 2018-19 और 2019-20 के दौरान एटीआई योजना के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के बाद सुधार लाए गए थे।

#### 5.1.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य और लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- (i) दिशानिर्देश, नीतिगत ढांचा और योजना पर्याप्त थे,
- (ii) योजना कार्यान्वयन कुशल और प्रभावी था,
- (iii) वित्तीय प्रबंधन कुशल था और उपलब्ध निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया था, और;
- (iv) आंतरिक नियंत्रण मौजूद थे और निगरानी प्रभावी थी

लेखापरीक्षा मानदंड थे: एटीआई योजना के दिशानिर्देश 2010 और 2016, स्क्रीनिंग समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, अनुमोदन पत्र, स्वीकृति आदेश और सामान्य वित्तीय नियम, 2005/2017

#### 5.1.1.5 लेखापरीक्षा नमूना

योजना के तहत निधि प्राप्त करने वाले 13 संस्थानों<sup>2</sup> में से, लेखापरीक्षा ने पांच कार्यान्वयन संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद, तेलंगाना; राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा, उत्तर प्रदेश; सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना, पंजाब; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), ओखला, दिल्ली और कर्नाटक उद्यमशीलता

<sup>2</sup> 1. एनआईएमएसएमई, योसुफगुडा, हैदराबाद; 2. एनआईईएसबीयूडी, नोएडा, उत्तर प्रदेश; 3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईई), गुवाहाटी, असम; 4. एनएसआईसी, ओखला, दिल्ली; 5. सीटीआर, लुधियाना, पंजाब; 6. सेडोक, धारवाड़, कर्नाटक; 7. वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (वीएमओयू), कोटा, राजस्थान; 8. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर, राजस्थान; 9. गुलबर्गा इंस्टीट्यूट एस्टेट मैनेज्मेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन (जीआईईएमए), गुलबर्गा, कर्नाटक; 10. उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई), जोट, अरुणाचल प्रदेश; 11. कॉयर बोर्ड, कोच्चि, केरल; 12. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद, गुजरात; और 13. उद्यमिता विकास एवं नवाचार संस्थान (ईडीआईआई), चेन्नई, तमिलनाडु

विकास केंद्र (सीईडीओके), धारवाड़, कर्नाटक की विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयन<sup>3</sup> किया।

### 5.1.1.6 लेखापरीक्षा के बाद सुधार

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए मंत्रालय स्तर पर लेखापरीक्षा के बाद योजना के निष्पादन में सुधार नीचे तालिका बद्ध हैं:

**तालिका 5.1: एटीआई योजना में लेखापरीक्षा के बाद सुधार**

कं. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	पैरा सं.	किए गए सुधार
1.	2012 से 2018 के दौरान, स्क्रीनिंग कमेटी (एससी) की बैठकों के कार्यवृत्त को हितधारकों के बीच परिचालित नहीं किया गया था, कार्यान्वयन संस्थानों के प्रतिनिधियों को बैठकों में आमंत्रित नहीं किया गया था और संस्थानों का निरीक्षण नहीं किया गया था। एससी ने केवल आठ बैठकें की थी।	5.1.2.4(क)	मंत्रालय ने शुरू किया है: <ul style="list-style-type: none"> <li>• एससी बैठकों के कार्यवृत्त का परिसंचरण</li> <li>• एससी बैठकों में कार्यान्वयन संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना शुरू किया और बैठकों की आवृत्ति में वृद्धि की</li> <li>• प्रशिक्षण संस्थानों<sup>4</sup> के निरीक्षण के लिए अपने अधिकारियों को भेजना</li> </ul>
2.	मंत्रालय ने एनएसआईसी और सीटीआर की तुलना में एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई को अधिकांश प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए	5.1.2.1(क)	2018-19 के बाद से, मंत्रालय ने एनआईएमएसएमई के प्रशिक्षण लक्ष्यों को कम किया और एनएसआईसी और सीटीआर की हिस्सेदारी बढ़ा दी
3.	प्रशिक्षण डाटा बेस में अनियमितताएं: डुप्लीकेशन के 12,746 मामले, अस्पष्ट डुप्लीकेशन के 16,884 मामले	5.1.2.2(घ)	2018-20 के दौरान, प्रति वर्ष डुप्लीकेशन के औसतन 49 मामले और अस्पष्ट डुप्लीकेशन के 65 मामले देखे गए, जबकि 2012-18 के दौरान प्रति वर्ष डुप्लीकेशन

<sup>3</sup> संस्थानों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर किया गया था, और संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुदान की मात्रा और उनके द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या के आधार पर स्तरों का गठन किया गया था।

<sup>4</sup> सीटीआर, लुधियाना; सीटीआर लुधियाना के प्रशिक्षण केंद्र (i) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआई), चेन्नई, (ii) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन (सीआईटीडी), हैदराबाद, (iii) इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद, (iv) सेंट्रल हस्त उपकरण संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर; एलबीआई, चेन्नई में एनएसआईसी, दिल्ली का प्रशिक्षण केंद्र; और एनआईएमएसएमई, हैदराबाद में निरीक्षण किया गया।

कं. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	पैरा सं.	किए गए सुधार
	और प्रशिक्षु नामों में अप्रासंगिक प्रविष्टियां देखी गईं।		के 2,124 मामले और अस्पष्ट डुप्लीकेशन के 2,814 मामले प्रति वर्ष पाए गए। 2012-18 के दौरान 25 अप्रासंगिक प्रविष्टियों की तुलना में 2018-20 के दौरान कोई अप्रासंगिक प्रविष्टियाँ नहीं पाई गईं।

### 5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दिए गए पैराग्राफों में दिया गया है:

#### 5.1.2.1 एटीआई योजना की आयोजना

##### क. संस्थानों की क्षमताओं का निर्धारण न करना

एटीआई योजना के दिशानिर्देश 2010 के पैरा 3.3.3 के अनुसार, स्क्रीनिंग कमेटी (एससी) को आवेदक प्रशिक्षण संस्थानों की योग्यता, क्षमता और अनुभव की जांच के लिए मानदंड निर्धारित करने थे। एससी को प्रस्तावों की उपयुक्तता, योग्यता, क्षमता, अनुभव / संस्थान के पूर्व निष्पादन, निधि की उपलब्धता आदि के आलोक में आवेदक संस्थानों के प्रस्तावों पर विचार करना था, और प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशों के साथ सचिव (एमएसएमई) को अग्रेषित करना था।

दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा एससी द्वारा किसी ऐसे मानदंड को निर्धारित करने या उस पर विचार करने के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशिक्षण लक्ष्य (अनुलग्नक-XXXII) संस्थानों को उनकी क्षमता और कर्मचारियों की संख्या पर विचार किए बिना आवंटित किए गए थे। उदाहरण<sup>5</sup> के तौर पर, 2012-13 व 2013-14 के दौरान संस्थानों की कुल स्टाफ संख्या (गैर-संकाय सहित) और प्रशिक्षण

<sup>5</sup> एनआईएमएसएमई, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई ने स्वयं के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भागीदार संस्थानों (पीआईज़) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। मंत्रालय ने केवल 2012-13 और 2013-14 के दौरान संस्थानों को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्यों को अपने कार्यक्रमों और पीआईज़ कार्यक्रमों में विभाजित किया और उसके बाद बिना किसी विभाजन के समेकित लक्ष्य आवंटित किए। इसके अलावा, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के लिए चयनित संस्थानों के पीआईज़ के स्टाफ की संख्या प्रस्तुत नहीं की। इसे देखते हुए, संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या (पीआईज़ को छोड़कर) की तुलना मंत्रालय द्वारा संस्थानों को अपने स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रम (यानी, पीआईज़ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को छोड़कर) के लिए आवंटित लक्ष्यों के साथ केवल दो वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 हेतु की गई थी।

कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवंटित लक्ष्यों की तुलनात्मक स्थिति को तालिका 5.2 में दिखाया गया है।

तालिका 5.2: आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना में संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या

संस्थान	संस्थान के कर्मचारियों की संख्या	सभी संस्थानों के कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत	2012-13 और 2013-14 में आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम	कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रतिशत
एनआईईएसबीयूडी	26	1.34	3,448	45.05
एनआईएमएसएमई	91	4.72	1,666	21.76
आईआईई	44	2.28	1,430	18.68
सीटीआर	870	45.08	628	8.20
एनएसआईसी	899	46.58	481	6.28
<b>कुल</b>	<b>1,930</b>	<b>100</b>	<b>7,653</b>	<b>100</b>

जैसा कि तालिका 5.2 से देखा जा सकता है, एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई को 2012-13 और 2013-14 के दौरान कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रमशः 45 प्रतिशत और 22 प्रतिशत आवंटित किया गया था, जबकि सभी पांच संस्थानों की कुल स्टाफ संख्या की तुलना में इनके कर्मचारियों की संख्या केवल 1.34 प्रतिशत और 4.72 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, सीटीआर और एनएसआईसी के पास पांच संस्थानों की कुल स्टाफ संख्या का 45 प्रतिशत और 47 प्रतिशत होने के बावजूद, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का केवल आठ प्रतिशत और छः प्रतिशत आवंटित किया गया था।

2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान, मंत्रालय ने एनआईईएसबीयूडी (37 प्रतिशत) और एनआईएमएसएमई (31 प्रतिशत) को अधिकांश प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए थे, जिन्होंने आगे अपने स्वयं के कार्यक्रमों के क्रमशः 99 प्रतिशत<sup>6</sup> और 92 प्रतिशत<sup>7</sup> को निजी एंजेसियो को आउटसोर्स किया था, जो कि एटीआई योजना के तहत प्रतिबंधित था। दूसरी ओर, एनएसआईसी (सात प्रतिशत) और सीटीआर (11 प्रतिशत) को उनकी बेहतर क्षमता और कर्मचारियों की संख्या के बावजूद अल्प कार्यक्रम आवंटित किए गए थे।

<sup>6</sup> कुल 3,776 कार्यक्रमों में से, एनआईईएसबीयूडी ने 3,756 कार्यक्रमों को आउटसोर्स किया

<sup>7</sup> कुल 3,438 कार्यक्रमों में से एनआईएमएसएमई ने 3,159 कार्यक्रमों को आउटसोर्स किया

मंत्रालय ने तर्क दिया (मार्च 2019) कि एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी उद्यमिता विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थान थे और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बड़ा हिस्सा दिया गया था। प्रशिक्षण एनएसआईसी के पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, और सीमित संख्या में कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल थे। सीटीआर ने लंबी अवधि के तकनीकी पाठ्यक्रम (1-3 वर्ष) आयोजित किए जो एटीआई योजना के तहत पाठ्यक्रमों से अलग थे, जो सामान्य रूप से 72-300 घंटे की अवधि के थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मात्र कर्मचारियों की संख्या प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता का निर्धारण नहीं कर सकती है और प्रशिक्षण लक्ष्य संस्थानों के प्रस्तावों, बजट की उपलब्धता और पिछले वर्ष में उनके निष्पादन के आधार पर निर्धारित किए गए थे। आगे यह भी बताया गया कि मंत्रालय को एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई द्वारा कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग की जानकारी नहीं थी।

मई 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इसके स्थानांतरण के अनुसरण में, 2016-17 से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एनआईईएसबीयूडी को कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने 2018-19 से एनआईएमएसएमई के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग को कम किया और एनएसआईसी और सीटीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि की।

#### **सिफारिश संख्या 1**

*किसी कार्यक्रम को मंजूरी देने से पहले, स्क्रीनिंग कमेटी की संस्था को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और इसके अपनाने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है।*

#### **ख. कौशल आवश्यकताओं का निर्धारण न करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों को मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार के न्यूनतम लक्ष्य आबंटित न करना**

लेखापरीक्षा को कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जो यह आश्वासन दे सके कि मंत्रालय ने देश में प्रचलित कौशल आवश्यकताओं, कौशल अंतराल का निर्धारण किया था, और तदनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से निश्चित कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अंतराल को कम करने की योजना बनाई थी। मंत्रालय के संस्वीकृति आदेशों में भी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्वदेशी उद्यमिता, मजदूरी रोजगार या प्रशिक्षुओं के स्वरोजगार के विकास

के मामले में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। एससी की किसी भी बैठक में प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं की रोजगारपरकता या रोजगार की स्थिति और स्वदेशी उद्यमिता के विकास पर चर्चा नहीं की गई। एटीआई योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभीष्ट परिणाम की उपलब्धि पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण के बाद आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए कोई तंत्र भी निर्धारित नहीं किया गया था। मंत्रालय, देश में नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास के बारे में लेखापरीक्षा के लिए कोई आंकड़ा पेश नहीं कर सका, जो इस योजना का मूल उद्देश्य था।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2019) कि प्रशिक्षुओं के रोजगार के लिए लक्ष्य सौंपना संभव नहीं था क्योंकि रोजगार सृजन आर्थिक विकास की स्थिति, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, और न कि अकेले प्रशिक्षण पर। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि योजना का मूल उद्देश्य उद्यमिता का आधार विकसित करना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना था। लेखापरीक्षा का मानना है कि उद्यमिता विकास (स्वरोजगार) या मजदूरी रोजगार के न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किए बिना योजना के परिणाम का निर्धारण करना संभव नहीं होगा। इसलिए, मंत्रालय का ध्यान देश में उद्यमशीलता के आधार को बढ़ाने पर होना चाहिए जिससे प्रशिक्षुओं की रोजगारपरकता में वृद्धि हो।

#### **सिफारिश संख्या 2**

मंत्रालय को निर्धारित और आवश्यक प्रत्येक प्रकार के कौशल सेटों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के आवश्यक न्यूनतम स्तरों को लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

#### **सिफारिश संख्या 3**

मंत्रालय को मंत्रालय/संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं की आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए एक तंत्र बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

### **5.1.2.2 योजना कार्यान्वयन**

क. वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान, मंत्रालय ने पांच सर्वोच्च संस्थानों को 17,615 प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किए, जिनमें 4,73,658 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य

है। इसके प्रति 15,263 कार्यक्रम (87 प्रतिशत) को 4,13,131 (87 प्रतिशत) व्यक्तियों के प्रशिक्षण के साथ पूरा किया गया, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धि

संस्थान	कार्यक्रम			प्रशिक्षु		
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
एनआईएसबीयूडी	6,558	5,274	80	1,64,020	1,32,562	81
एनआईएमएसएमई	5,385	4,990	93	1,59,345	1,47,333	92
आईआईई	2,464	2,026	82	72,830	61,319	84
सीटीआर	1,903	1,812	95	47,575	45,764	96
एनएसआईसी	1,305	1,161	89	29,888	26,153	88
<b>कुल</b>	<b>17,615</b>	<b>15,263</b>	<b>87</b>	<b>4,73,658</b>	<b>4,13,131</b>	<b>87</b>

#### ख. सर्वोच्च संस्थानों द्वारा स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग

मंत्रालय के संस्वीकृति आदेशों में यह निर्धारित किया गया था कि कोई संस्थान अपने आप या अनुमोदित साझेदार संस्थानों (पीआईज़)<sup>8</sup> के माध्यम से सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगा। संस्थान, एटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार पीआईज़ का चयन करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि, उन्हें अन्य एजेंसी को कार्यक्रमों को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई ने संस्वीकृति आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यक्रमों को पीआईज़ के अलावा अन्य निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई ने आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फैकल्टी को कार्य पर रखा और उनके चयन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यहां तक कि प्रशिक्षुओं और फैकल्टी का चयन भी आउटसोर्स एजेंसियों पर छोड़ दिया गया। लेखापरीक्षा, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फैकल्टी की योग्यताओं का सत्यापन नहीं कर सका और इस प्रकार, कार्य पर लगाई गई फैकल्टी की सक्षमता और कार्यक्रमों में प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

<sup>8</sup> यदि किसी संस्थान के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी, तो उसके पास अपनी अधिकृत पीआईज़ को अपनी क्षमता से अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम आवंटित करने और उसे पूरा करने का विकल्प था।



मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसंबर 2019) कि उसे संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटसोर्सिंग के बारे में जानकारी नहीं थी।

### ग. एनआईईएसबीयूडी के आउटसोर्स कार्यक्रमों में देखी गई अनियमितताएं

एनआईईएसबीयूडी के नोएडा परिसर में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला है कि एनआईईएसबीयूडी ने सभी उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपी) को अननुमोदित निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया था। इसने अपनी ओर से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से फैकल्टी, बुनियादी ढांचा और समन्वयक प्रदान करने के लिए तीन विभिन्न निजी एजेंसियों को कार्य पर रखा। 19 मामलों की नमूना जांच से पता चला कि इन सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी (एनआईईएसबीयूडी के महानिदेशक) ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद निजी एजेंसियों के चयन और नियुक्तियों को अनुमोदित किया। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले कार्य आदेश जारी कर दिए गए थे। एक मामले में कार्यक्रम पूरा होने के बाद कार्य पर लगाई गई एजेंसियों (सभी तीनों) को कार्य आदेश जारी किया गया था।

एनआईईएसबीयूडी ने कहा (नवंबर 2019) कि कार्यक्रमों को, उसी वित्तीय वर्ष के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत शुरू करने के निर्देशों के साथ आवंटित किया गया था। तदनुसार, कार्यक्रम समन्वयक विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों को लामबंद करने के लिए तुरंत कार्यक्षेत्र में चले गए। उम्मीदवारों के चयन और अवसंरचना और फैकल्टी को अंतिम रूप देने के बाद फाइलों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, कई मामलों में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किए गए; हालांकि, सक्षम प्राधिकारी के मौखिक निर्देश पहले से प्राप्त किए गए थे। सक्षम प्राधिकारी ने अपनी संतुष्टि के बाद फाइलों पर हस्ताक्षर किए।

उत्तर अस्वीकार्य है, क्योंकि लेखापरीक्षा को ऐसे किसी भी निर्देश की सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई पुष्टि नहीं मिल सकी।

आगामी संवीक्षा से पता चला कि छह मामलों में, तीन एजेंसियों (अवसंरचना प्रोवाइडर, फैकल्टी प्रोवाइडर और कोऑर्डिनेटर प्रोवाइडर) जिन्होंने एनआईईएसबीयूडी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए और अलग बीजक प्रस्तुत किए, अपने-अपने बीजकों में एक ही तरह की गलतियां कीं और एक ही प्रकार से उन गलतियों को सुधारा। यह तभी संभव

था जब एक ही व्यक्ति ने बीजक तैयार किया हो और सुधार किया हो। ऐसे दो उदाहरण, संदर्भ के लिए नीचे बॉक्स 5.1 में पुनः दिए गए हैं।

बॉक्स 5.1: बीजकों का वह हिस्सा जहां कार्यक्रम 2012/5824 & 5825 & 2014/22531 & 22532 में गलती की गई थी

**क. कार्यक्रमों 2012/5824 और 5825 के बीजक जहां तीनों एजेंसियों ने एक ही गलती की और अपने अलग बीजक में एक ही तरह से सुधार किया अवसंरचना प्रदाता का बीजक - जीआईआईटी**

Sub:- Invoice for providing class room, furniture & training aids .	
Codes:- 2012/5824 & 2012/5825	Category:-General
Prog :- Finishing & packaging supervisor	Date :- 05-03-12 to 11-04-12
Duration :- 125 Hrs	Venue:-Loni
No of Trainee:- 25 Each	

➤ फैकल्टी प्रदाता का बीजक - पैनोरमा यूनिवर्सल

Sub:- Invoice for providing faculty support in training programmes.	
Codes:- 2012/5824 & 2012/5825	Category:-General
Prog :- Finishing & packaging supervisor	Date :- 05-03-12 to 11-04-12
Duration :- 125 Hrs	Venue :-Loni
No of Trainee:- 25 Each	

➤ समन्वयक प्रदाता का बीजक - प्रोमिनेन्ट सोल्यूशन

Sub:- Invoice for providing coordinator support and expenses on various activities	
Codes:- 2012/5824 & 2012/5825	Category:-General
Prog :- Finishing & packaging supervisor	Date :- 05-03-12 to 11-04-12
Duration :- 125 Hrs	Venue :-Loni
No of Trainee:- 25 Each	

**ख. कार्यक्रमों के बीजक 2014/22531 और 22532 जहां तीनों एजेंसियों ने एक ही गलती की और अपने अलग बीजक में एक ही तरह के अंदाज में सुधार किया**

➤ अवसंरचना प्रदाता का बीजक - एडुवेव रिवोल्यूशन

Sub:- Invoice for 2 Skill Development Training Programme for SC and GENERAL candidates.	
Prog Details :- 22531, 22532	Prog Name : Repair and Maintenance of Power supply, Inverter and UPS
Duration :- 300 Hrs	Date : 21-12-2015 to 23-03-2016
No of Trainees:- 25 each prog.	Venue : Hardoi & Jaunpur

➤ फैकल्टी प्रोवाइडर का बीजक - सृष्टि सेवा समिति

Sub:- Faculty Support Invoice for 2 Skill Development Training Programme for SC and GENERAL candidates.	
Prog Details :- 22531, 22532	Prog Name : Repair and Maintenance of Power supply, Inverter and UPS
Duration :- 300 Hrs	Date : 21-12-2015 to 23-03-2016
No of Trainees:- 25 each prog.	Venue : Hardoi & Jaunpur

➤ समन्वयक प्रदाता का बीजक - ग्रामीण युवाओं के सशक्तिकरण के लिए संगठन

Sub:- Invoice for 2 Skill Development Training Programme for SC and GENERAL candidates.	
Prog Details :- 22531, 22532	Prog Name : Repair and Maintenance of Power supply, Inverter and UPS
Duration :- 300 Hrs	Date : 21-12-2015 to 23-03-2016
No of Trainees:- 25 each prog.	Venue : Hardoi & Jaunpur

एनआईईएसबीयूडी ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि तीनों एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम की एक ही गलत तिथि छापने की त्रुटि इसलिए थी क्योंकि कार्यक्रम के एक अकेले समन्वयक ने इन बीजकों को तैयार करने में तीनों एजेंसियों की सहायता की थी और त्रुटियों को हाथ से ठीक किया गया था।

ऊपर दिए गए तथ्यों से, कुछ कार्यक्रमों में एनआईईएसबीयूडी द्वारा इन-हाउस बीजकों और अभिलेखों के निर्माण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2019) कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

#### घ. अज्ञात उम्मीदवारों पर संदिग्ध व्यय

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से 2012-13 से 2017-18 की अवधि के लिए एटीआई योजना के तहत प्रशिक्षण/प्रशिक्षुओं का पूरा डेटा<sup>9</sup> उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (जून 2018)। मंत्रालय ने एक वर्ष बाद आंकड़े उपलब्ध कराए (मई 2019), जो अधूरे थे। आंकड़ों में अभिलेखों के अनुसार प्रशिक्षित कुल 4,01,927 प्रशिक्षुओं में से केवल 2,80,017 प्रशिक्षुओं (70 प्रतिशत) की जानकारी निहित थी। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में लिंग, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण के लिए प्रतिपूर्ति और प्रशिक्षुओं के आधार नंबरों के बारे में जानकारी गायब थी। 25 मामलों में, प्रशिक्षु डेटा अप्रासंगिक था क्योंकि प्रशिक्षुओं और उनके पिता के नाम या तो संख्याओं में थे या अस्त-व्यस्त वर्णमाला (अर्थात् ईई, एए, 000 000, 99999, ए बी, वाई पी, पी आर, एबीसी आदि) में थे। इन 25 मामलों में, संस्थानों ने मंत्रालय से ₹10.70 लाख का दावा किया था।

प्रशिक्षण आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण करने और योजना कार्यान्वयन के बेहतर मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से 2012-13 से 2019-20 की अवधि के लिए एटीआई योजना प्रशिक्षणों का पूरा आधार-लिंकड डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया (अगस्त 2019)। मंत्रालय ने सितंबर 2020 में एक तालिका में आंकड़े उपलब्ध कराए थे। मंत्रालय ने इस बार 4,19,722 प्रशिक्षुओं<sup>10</sup> के संबंधित आंकड़े बिना आधार और प्रशिक्षुओं के मोबाइल नंबर के उपलब्ध कराए।

<sup>9</sup> एआईटी प्रशिक्षण वेबसाइट [msmetraining.gov.in](http://msmetraining.gov.in) का डाटा ड्रॉप

<sup>10</sup> लेखापरीक्षा में देखे गए अभिलेखों के अनुसार, 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान, पांच संस्थानों द्वारा 4,13,131 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था, जैसा कि सब पैरा 5.1.2.2 (क) के तहत तालिका 5.3 में दिखाया गया है। हालांकि, सितंबर 2020 में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कुल 4,19,722 प्रशिक्षु दर्शाए गए। इस प्रकार, अभिलेखों के अनुसार आंकड़ों और मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के बीच विसंगति थी।

डेटा विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

### i) डुप्लीकेट प्रशिक्षु

लेखापरीक्षा ने 4,19,722 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षु के नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि की तुलना की और 12,844 डुप्लीकेट मामले पाए (अनुलग्नक-XXXIII)। सबसे ज्यादा डुप्लीकेट प्रशिक्षुओं (4,482 प्रशिक्षु) की संख्या वर्ष 2012-13 में थी और सबसे कम वर्ष 2019-20 (41 प्रशिक्षु) में थी। डुप्लीकेट की पुनरावृत्ति की आवृत्ति दो से नौ बार थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2015-16 के बाद से डुप्लीकेट के मामलों की संख्या में कमी आई। लेखापरीक्षा में सर्वोच्च संस्थानों और उनके पीआईज़ के बीच और विभिन्न संस्थानों के बीच भी प्रशिक्षुओं के डुप्लीकेशन के मामलों को भी देखा गया। कार्यक्रम या तो एक ही स्टेशन पर या एक दूसरे से दूर स्थित स्टेशनों पर आयोजित किए गए थे, और सभी मामलों में कार्यक्रमों की अवधि या तो बिल्कुल एक जैसी थी या अतिव्यापी थी। 12,844 डुप्लीकेट मामलों के संबंध में प्रशिक्षण की अनुमानित लागत ₹12.75 करोड़<sup>11</sup> थी।

एनआईईएसबीयूडी और सीटीआर ने कहा (अगस्त 2019) कि एक प्रशिक्षु के लिए उसी दिन या उसी अवधि में एक और स्लॉट पर, दूसरी पाली में एक और प्रशिक्षण में भाग लेना संभव है, क्योंकि सभी प्रशिक्षण पूरे दिन के लिए नहीं थे। एनआईईएसबीयूडी ने आगे कहा कि एक ही दिन एक उम्मीदवार को अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं था।

एनआईईएसबीयूडी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में देखा गया है कि एनआईईएसबीयूडी के दो कार्यक्रमों में (6 अगस्त 2012 से 8 नवंबर 2012 में आयोजित हापुड़, उत्तर प्रदेश का 2012/9050 और 1 अगस्त 2012 से 31 अक्टूबर 2012 के दौरान आयोजित, संगरूर, पंजाब का 2012/8583, जहां कार्यक्रमों की अवधि अतिव्यापी थी, 25 में से 16 उम्मीदवारों ने दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया था, यद्यपि दोनों कार्यक्रमों का

<sup>11</sup> 12,844 डुप्लीकेट मामलों के संबंध में प्रशिक्षण की लागत का अनुमान लगाने के लिए, 86 प्रशिक्षुओं के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और इन 86 मामलों में प्रति प्रशिक्षु औसत लागत ₹9,928/- पाई गई। इस प्रकार, 12,844 डुप्लीकेट मामलों में शामिल कुल राशि को ₹12.75 करोड़ (12,844 \* ₹9,928) माना जा सकता है।

विषय एक ही था अर्थात 'एसी रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर रिपेयर' और कार्यक्रमों के प्रशिक्षण स्थलों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर से अधिक थी।

## ii) अस्पष्ट डुप्लिकेट प्रशिक्षु

अस्पष्ट डुप्लिकेट वे हैं जहां प्रशिक्षु और/या पिता के नाम मामूली परिवर्तन के साथ अलग दिखाई देते हैं।

लेखापरीक्षा ने 4,19,722 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षु नामों और पिता के नामों की तुलना<sup>12</sup> की और 17,014 अस्पष्ट डुप्लिकेट मामले पाए। सबसे अधिक मामले 2014-15 (5,429) से संबंधित थे और 2019-20 (65) के लिए सबसे कम थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2015-16 के बाद से, अस्पष्ट डुप्लिकेट प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी आई। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी संस्थानों के कार्यक्रमों में अस्पष्ट डुप्लिसिटी मौजूद थी। संस्थान-वार अस्पष्ट डुप्लिकेट मामलों का विवरण (अनुलग्नक-XXXIV) में हैं।

एनआईईएसबीयूडी ने कहा (अगस्त 2019) कि प्रशिक्षु डेटा अपलोड करते समय समस्या सॉफ्टवेयर की हो सकती है और भविष्य में ऐसे उदाहरणों से बचने के लिए उचित देखभाल का आश्वासन दिया। हालांकि, एनआईईएसबीयूडी ने अपने तर्क या सॉफ्टवेयर डिजाइन में समस्याओं के बारे में इसके द्वारा की गई शिकायत के समर्थन में कोई सबूत संलग्न नहीं किया।

सीटीआर ने कहा (अगस्त 2019) कि इसके क्षेत्रों में व्यक्तियों के नाम थोड़े भिन्न हैं। कई बार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही नाम या पिता का नाम समान हो सकता है लेकिन व्यक्तियों को अलग चिन्हित किया गया था और यह जानबूझकर प्रशिक्षुओं या उनके पिता के नाम में फेरबदल नहीं कर रहा था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आंकड़ों में हेरफेर का संकेत मिलता है। अन्य संस्थानों ने अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

---

<sup>12</sup> ऐसे अस्पष्ट डुप्लिकेट मामलों का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने प्रशिक्षुओं और उनके पिताओं के नामों की तुलना 95 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम के मिलान के मापदंड से की। जन्म तिथि को मिलान के लिए एक कसौटी के रूप में नहीं लिया गया था, क्योंकि अस्पष्ट मिलान तारीखों के साथ प्रभावी नहीं होता।

डुप्लीकेट प्रशिक्षुओं और अस्पष्ट डुप्लीकेट प्रशिक्षुओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाई गई गंभीर अनियमितताओं को स्वीकार किया (नवंबर 2019) और कहा कि इन्हें ठीक किए जाने की आवश्यकता है और प्रशिक्षण संस्थानों के परामर्श से और सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने संस्थानों को उचित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आश्वासन दिया कि अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

### iii) अभिलेखों का भौतिक सत्यापन

डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए, लेखापरीक्षा ने एनआईईएसबीयूडी के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने संवीक्षा के लिए 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए 64 कार्यक्रम फाइलों का चयन किया। हालांकि, एनआईईएसबीयूडी ने लेखापरीक्षा को केवल 39 मूल कार्यक्रम फाइलें प्रस्तुत कीं और प्रस्तुत किए गए शेष 25 कार्यक्रम रिकॉर्ड एमएसएमई प्रशिक्षण वेबसाइट ([msmetraining.gov.in](http://msmetraining.gov.in)) से केवल प्रिंटआउट ही थे। इनमें अटेंडेंस शीट, ओरिजनल एडमिशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, फैकल्टी डिटेल्स आदि शामिल नहीं थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं कर सकी।

उत्तर में एनआईईएसबीयूडी ने कहा (जुलाई 2020) कि मूल कार्यक्रम फाइलों को खोजने के लिए संस्थान के प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि वे बहुत पुराने थे (वित्त वर्ष 2012-13 से 2015-16)।

39 मूल कार्यक्रम फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि तीन कार्यक्रम सं. 2013/14613 (कोलकाता में उद्यमिता विकास कार्यक्रम), 2015/22413 (सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में फैशन डिजाइनिंग कार्यक्रम) और 2015/22470 (मध्य प्रदेश के सीधी में फैशन डिजाइनिंग कार्यक्रम) में मिले दस्तावेज<sup>13</sup>, तीन अन्य कार्यक्रम फाइलों क्रमशः 2014/17207 (इंटीरियर डिजाइन कार्यक्रम, हावड़ा, पश्चिम बंगाल), 2014/22083 (सोलन, हिमाचल प्रदेश में रखरखाव फिटर कार्यक्रम) और 2015/17599 (मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वेब डिजाइनिंग कार्यक्रम) में मिले दस्तावेजों की सटीक प्रतियां थीं। यह स्पष्ट है कि एनआईईएसबीयूडी ने प्रशिक्षण वेबसाइट पर एक से अधिक बार प्रशिक्षुओं के एक ही सेट का विवरण अपलोड किया और गलत तरीके से सहायता का दावा किया।

<sup>13</sup> अटेंडेंस शीट, प्रशिक्षु आवेदन फॉर्म, प्रशिक्षु के सहायक दस्तावेज, प्रतिपुष्टि फॉर्म आदि



प्रशिक्षुओं के आधार से जुड़े आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या आधार लिंकिंग (2016-17 में शुरू की गई) ने मंत्रालय को पहले पहचानी गई गंभीर अनियमित प्रथाओं को जड़ से मिटाने में मदद की थी। आधार से जुड़े डेटा को साझा करने में मंत्रालय की अनिच्छा के कारण, लेखापरीक्षा, ऊपर उल्लिखित चिन्हित मामलों के प्रभाव का निर्धारण करने और प्रशिक्षण कोषों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक किसी भी सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने में असमर्थ है।

#### **सिफारिश संख्या 4**

मंत्रालय, गुणवत्ता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और शामिल एजेंसियों का ई-केवाईसी सत्यापन शुरू करने पर विचार कर सकता है।

#### **सिफारिश संख्या 5**

इस प्रतिवेदन में उजागर अनियमितताओं/खामियों की जांच की जाए और ऐसी खामियों के लिए संबंधित अधिकारियों/संस्थानों की जिम्मेदारी मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाए।

### **5.1.2.3 निधि प्रबंधन**

#### **क. मंत्रालय को सूचित नहीं की गई प्रशिक्षण निधियों का अव्ययित शेष**

लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2017-18 के दौरान, एटीआई योजना के तहत नमूना चयनित सर्वोच्च संस्थानों द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि का सत्यापन किया और पाया कि एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी के पास 31 मार्च, 2018 तक क्रमशः ₹1.27 करोड़ और ₹2.78 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी। संस्थानों ने मंत्रालय को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसीज़) में अनुदानों और अर्जित ब्याज का अव्ययित शेष घोषित नहीं किया था। इस प्रकार, एनआईएमएसएमई और एनआईईएसबीयूडी ने यूसीज़ में ₹4.05 करोड़ कम दिखाए। इनका विवरण **अनुलग्नक-XXXV** में हैं।

मार्च 2019 में, एनआईएमएसएमई ने कहा कि उसने मंत्रालय से प्राप्त निधियों के प्रति यूसी को प्रस्तुत किया था और ब्याज के हिस्से के लिए एक और यूसी को प्रस्तुत करेगा। इसमें आगे कहा गया है कि अक्टूबर 2018 में 2017-18 के अव्ययित शेष के रूप में

मंत्रालय को ₹52.89 लाख लौटाए गए थे। हालांकि, मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार एनआईएमएसएमई ने कोई राशि वापस नहीं की थी (सितंबर 2020)।

एनआईएमएसबीयूडी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2019) कि उसने अव्ययित शेष राशि (₹0.96 करोड़) और ब्याज (₹1.83 करोड़) दोनों को अपने पास रखा, जिसे अवसर लागत<sup>14</sup> के लिए मुआवजे के रूप में माना गया।

एनआईएमएसबीयूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही मॉनिटरिंग और हैंडहोल्डिंग पर व्यय का लाभ उठाया था।

मंत्रालय ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2019) कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

#### 5.1.2.4 योजना की मॉनिटरिंग और प्रभाव

##### क. मंत्रालय स्तर पर एटीआई योजना की मॉनिटरिंग

दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार, एक स्क्रीनिंग समिति (एससी) जिसमें मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकारी और सचिव (एमएसएमई) थे, को समय-समय पर एटीआई योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता थी। हालांकि, दिशा-निर्देशों में मॉनिटरिंग तंत्र का ब्यौरा निर्धारित नहीं किया गया था। 2012-13 से 2017-18 के दौरान, एससी ने कार्यान्वयन संस्थानों से कोई प्रतिनिधित्व के बिना केवल आठ बैठकें कीं थीं। एससी की बैठकों के विचार-विमर्श, 2017-18 तक कार्यान्वयन संस्थानों में प्रचारित नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने उपरोक्त अवधि के दौरान कोई तृतीय-पक्ष समीक्षा नहीं की। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 2012-13 से 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा<sup>15</sup> कभी नहीं किया जिससे एटीआई प्रशिक्षण की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा सके।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2019) कि 2019 के बाद से, इसने अधिक मात्रा में बैठकें बुलाई और सभी हितधारकों को कार्यवृत्त प्रचारित किए।

<sup>14</sup> अवसर लागत, या वैकल्पिक लागत, उस लाभ की हानि है जो तब प्राप्त होता यदि प्रदत्त विकल्प नहीं दिया जाता।

<sup>15</sup> योजना दिशा-निर्देश 2010 के पैरा 3.3.3 (iv) के अनुसार, केंद्र सरकार और/या संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ईडीआई भी अपने कार्यालय के माध्यम से या किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ऐसी और जांच या सत्यापन कर सकती है, जैसा कि आवश्यक समझा जाता है।



वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने मंत्रालय के दावे की पुष्टि की।

## ख. संस्थानों के स्तर पर अपर्याप्त मॉनिटरिंग

### i) एनआईएमएसएमई द्वारा मॉनिटरिंग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईएमएसएमई ने प्रशिक्षण के बाद की अनुवर्ती गतिविधि सहित अपनी पीआईज़ और आउटसोर्स एजेंसियों को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन की मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार फैकल्टी सदस्यों की पहचान की। कार्यक्रम पूरा होने पर, फैकल्टी प्रभारी भुगतान पास करने के लिए दस्तावेज प्रमाणित करते थे। साथ ही, एनआईएमएसएमई द्वारा अपने पीआईज़ के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार, एनआईएमएसएमई का दायित्व था कि वह पीआई के प्रशिक्षकों/कोर फैकल्टी को प्रशिक्षण प्रदान करे और पीआई द्वारा नामांकित प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन/पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए।

हालांकि, एनआईएमएसएमई ने लेखापरीक्षा को पीआईज़ के फैकल्टी प्रशिक्षण के समर्थन में या पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए पीआईज़ की सहायता के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया। मॉनिटरिंग के लिए पीआईज़ का दौरा करने वाले फैकल्टी प्रभारी का कोई प्रमाण नहीं था।

उत्तर (अक्टूबर 2018) में, एनआईएमएसएमई ने कहा कि इसके अधिकारी, उद्घाटन और समापन सत्रों के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान पीआईज़ का दौरा करते थे। हालांकि, एनआईएमएसएमई ने कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

### ii) एनआईईएसबीयूडी द्वारा अपने स्वयं की और पीआईज़ कार्यक्रमों की अपर्याप्त मॉनिटरिंग

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एनआईईएसबीयूडी के नोएडा परिसर ने अपने स्वयं के कार्यक्रमों का 99 प्रतिशत निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाइलों में पूर्णता रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट/प्रमाण पत्र आदि शामिल नहीं थे। इसके अलावा, एनआईईएसबीयूडी ने पीआईज़ द्वारा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और निष्पादन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। जनवरी 2019 में, एनआईईएसबीयूडी ने पीआईज़ की मॉनिटरिंग के समर्थन में तीन दौरा रिपोर्टें प्रदान कीं। हालांकि, इन रिपोर्टों में मॉनिटरिंग किए गए कार्यक्रमों का कोई विशिष्ट विवरण नहीं था।

### ग. प्रशिक्षुओं को रोजगार

एटीआई योजना का मूल उद्देश्य देश में उद्यमिता का आधार विकसित करना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना था। इस उद्देश्य के लिए, अप्रैल 2012 से मार्च 2018 तक एटीआई योजना के तहत 4,01,927 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था और उसमें से लगभग 36 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को मंत्रालय के उत्तर के अनुसार रोजगार मिला था। मंत्रालय और सर्वोच्च संस्थानों से एकत्र किए गए प्रशिक्षुओं के रोजगार के आंकड़े तालिका 5.4 में दिए गए हैं:

**तालिका 5.4: संस्थानवार रोजगार के आंकड़े**

संस्थान	मंत्रालय से जुटाए गए रोजगार के आंकड़े		संस्थानों से एकत्र रोजगार के आंकड़े	
	मजदूरी रोजगार	स्वरोजगार	मजदूरी रोजगार	स्वरोजगार
एनआईएमएसएमई	48,465	28,239	41,654	27,245
एनआईईएसबीयूडी	38,064	5,513	23,905	10,988
सीटीआर	1,711	1,504	2,908	1,842
एनएसआईसी	3,281	2,133	2,977	3,608
आईआईई	7,145	6,721	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
<b>कुल (प्रतिशत<sup>16</sup>)</b>	<b>98,666 (25%)</b>	<b>44,110 (11%)</b>	<b>71,444 (18%)</b>	<b>43,683 (11%)</b>

इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि मंत्रालय और संस्थानों के रोजगार के आंकड़े मेल नहीं खाते हैं। मंत्रालय और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार आंकड़ों के विभिन्न सेटों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा, संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों से रोजगार सृजन की सीमा के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। इसके अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा सृजित रोजगार की सीमा और अधिकतम रोजगार देने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा, मंत्रालय, एटीआई योजना के क्रियान्वयन से देश में उद्यमिता आधार के विकास के बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर सका।

रोजगार और रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं:

<sup>16</sup> 2012-18 के दौरान संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित कुल 4,01,927 प्रशिक्षुओं के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं

- एनएसआईसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि रोजगार मेलों का आयोजन नियमित रूप से केंद्रों पर किया जाता था जहां उद्योगों का समूह, छात्रों के साक्षात्कार के लिए सहमत होता था। 2017-18 में एनएसआईसी के तकनीकी केंद्रों का 300 से अधिक कंपनियों ने दौरा किया।
- सीटीआर ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि 4,379 नियोक्ताओं को संपर्क पोर्टल में पंजीकृत प्रशिक्षुओं की भर्ती करने का अनुरोध किया गया था जिसमें उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की जानकारी थी।
- एनआईईएसबीयूडी ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि इसके द्वारा प्रशिक्षित लगभग 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने देश भर में 25 रोजगार मेलों में भाग लिया जिसमें 3 प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने स्वरोजगार चुना और 8-10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने मजदूरी रोजगार को चुना।
- मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि सर्वोच्च संस्थानों से मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उचित डेटा बनाए रखने की उम्मीद थी। भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को नोट किया गया है और प्रशिक्षण संस्थानों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार, प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में 36 प्रतिशत रोजगार सृजन के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, मंत्रालय ने एटीआई योजना के कारण उद्यमशीलता के आधार में वृद्धि के संबंध में जानकारी नहीं ली थी।

#### **सिफारिश संख्या 6**

योजना के दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे पर्याप्त विस्तृत निर्देश दिए जा सकें कि उद्यमिता या रोजगार के माध्यम से प्रशिक्षण को आजीविका में बदलने और चरणों में इसे प्राप्त करने के उद्देश्यों को कैसे तर्कसंगत बनाया जाए।

#### **5.1.3 निष्कर्ष**

मंत्रालय अपर्याप्त मॉनिटरिंग और खराब कार्यान्वयन के कारण इस योजना के परिकल्पित परिणामों को प्राप्त करने में काफी हद तक विफल रहा जिसके कारण संस्थानों द्वारा अनैतिक प्रथाओं का अनुसरण किया गया। मंत्रालय ने संस्थानों को उनकी क्षमता का निर्धारण किए बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किए। मंत्रालय द्वारा मॉनिटरिंग मापदंडों

को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया था जिससे संस्थानों को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और प्रशिक्षु अभिलेखों में हेराफेरी करने, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में छेड़छाड़ आदि करने जैसे अनैतिक तरीके अपनाने का साहस हुआ, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण और अभिलेखों की संवीक्षा के माध्यम से स्पष्ट है। इसके अलावा, एनआईईएसबीयूडी और एनआईएमएसएमई ने अव्ययित अनुदान और उस पर अर्जित ₹4.05 करोड़ के ब्याज का लेखांकन नहीं किया।

मंत्रालय ने इस बात का निर्धारण नहीं किया कि किस प्रकार के कौशल से बाजार में रोजगारपरकता बढ़ सकती है। मंत्रालय के संस्वीकृति आदेशों में भी संस्थानों के लिए स्वदेशी उद्यमिता के विकास या प्रशिक्षुओं के मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, न तो एटीआई योजना में प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण के बाद आजीविका की स्थिति के निर्धारण के लिए कोई तंत्र निर्धारित किया गया था और न ही स्क्रीनिंग समिति की किसी भी बैठक में ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा, योजना के अभीष्ट परिणाम की उपलब्धि पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

#### एमएसएमई विकास संस्थान, नागपुर

### 5.2 परियोजना के निष्पादन पर निष्फल व्यय

सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना की अनुचित योजना और निष्पादन के परिणामस्वरूप योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया, और ₹8.89 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, जिसमें भारत सरकार का ₹5.67 करोड़ का अनुदान शामिल है।

भारत सरकार (जीओआई) ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईज़) की क्षमता निर्माण और उनकी सामूहिकता के उद्देश्य से 'सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)' नामक एक योजना की शुरुआत की। एक क्लस्टर, एक पहचाने गए क्षेत्र के भीतर स्थित और समान उत्पादों/सेवाओं का उत्पादन करने वाले उद्यमों का एक समूह है। एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना करना इस योजना का एक अभिन्न हिस्सा था जो एमएसईज़ को अपने संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा और सार्वजनिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच, ऋण के लिए लिंकेज और विपणन

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में भी सक्षम होगा। इस योजना में, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, विपणन, कच्चे माल डिपो, बहिस्त्राव उपचार, पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं, परीक्षण प्रयोगशाला आदि के लिए साझा केंद्रों को शामिल करते हुए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई थी।

एमएसएमई मंत्रालय ने ₹15.38 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फ्लाई ऐश क्लस्टर में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2011), जिसमें ₹13.50 करोड़ की भारत सरकार की सहायता और ₹1.88 करोड़ का एसपीवी अंशदान शामिल था। परियोजना घटकों में, संयंत्र और मशीनरी (₹13.42 करोड़), भूमि और स्थल विकास (₹35 लाख), भवन और सिविल कार्य (₹40 लाख), विविध चल परिसंपत्ति (₹10 लाख), प्रारंभिक खर्च (₹15 लाख), परिचालन पूर्व खर्च (₹20 लाख), आकस्मिकताएं (₹64.48 लाख) और कार्यशील पूंजी मार्जिन (₹11.56 लाख) शामिल थे। सीएफसी को प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि से 24 महीने की अवधि के भीतर कार्य शुरू करना था, और उम्मीद थी कि वह क्लस्टर में उद्यमों को सस्ती लागत पर सामान्य सेवाएं प्रदान करेगा और साथ ही पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/विस्तार के लिए अपने सभी चालू व्यय, मूल्यहास और प्रावधान को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करेगा।

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमआईडीसी), मुंबई, परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी और मेसर्स हाई फ्लाई ऐश क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रपुर (एसपीवी) को अपने सदस्यों के उपयोग और लाभ के लिए सीएफसी को चलाना और बनाए रखना था। सीएफसी और उसकी मॉनिटरिंग का स्वामित्व महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के पास था। परियोजना की प्रगति के समन्वय और देखरेख के लिए एमएसएमई-विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई), नागपुर के निदेशक सर्वोच्च निकाय थे।

प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एसपीवी के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त जारी की जानी थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और पहली किस्त के व्यय विवरण, राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी और एमएसएमई-डीआई द्वारा सीएफसी की प्रगति पर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और खरीदी जाने वाली मशीनरी की सूची प्राप्त होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जानी थी।

सीएफसी के परिचालन से अपेक्षित परिणाम इस प्रकार थे:

क) एमएसई फ्लाइं ऐश प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या - 42 मौजूदा इकाइयां और विस्तार और विविधीकरण परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से अतिरिक्त 50 इकाइयां, और नए स्टार्ट-अप,

ख) उत्पादन - क्लस्टर कारोबार में ₹10 करोड़ से ₹70 करोड़ की वृद्धि। इसके अलावा, मौजूदा शून्य निर्यात की स्थिति को कम से कम 15 प्रतिशत निर्यात में बदलाव की संभावना थी,

ग) रोजगार सृजन - रोजगार में 1,100 से कम से कम 2000 व्यक्तियों की वृद्धि विकास आयुक्त, एमएसएमई, नई दिल्ली ने एमआईडीसी को ₹8.10 करोड़ की पहली किस्त जारी की (फरवरी 2012)। सीएफसी पर कुल व्यय ₹8.89 करोड़ (भारत सरकार का अनुदान: ₹5.67 करोड़ और एसपीवी का अंशदान: ₹3.22 करोड़) था। ₹2.43 करोड़ का अव्ययित अनुदान, एमएसएमई मंत्रालय को सरेंडर कर दिया गया था (अक्टूबर 2013)।

रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2016) और एमएसएमई-डीआई, नागपुर से एकत्र की गई जानकारी (अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021) से पता चला है कि हालांकि, सीएफसी को अल्प अवधि के लिए 2014, 2015 और 2017 के दौरान आंशिक रूप से परिचालन (ट्रायल रन) में लाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने अनुदान की शेष राशि जारी नहीं की क्योंकि एमएसएमई-डीआई द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में सीएफसी की योजना और कार्यान्वयन में निम्नलिखित खामियों को बताया गया था (दिसंबर 2014):

- परियोजना के अनुमोदन के समय, एसपीवी ने एसपीवी के सदस्यों के रूप में 42 मौजूदा फ्लाइं ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों को दिखाया था। हालांकि, निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि केवल तीन एसपीवी सदस्यों के पास ही फ्लाइं ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयां थीं, और शेष सदस्य केवल प्रस्तावित इकाइयां थीं।

- सीएफसी में स्थापित फ्लाई ऐश क्लासिफायर की क्षमता वर्गीकृत ऐश की प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन थी, लेकिन एसपीवी के तीन सदस्य प्रतिदिन केवल 20 मीट्रिक टन का उपयोग कर रहे थे।
- निरीक्षण के समय, चंद्रपुर और उसके आसपास 70-75 फ्लाई ऐश आधारित इकाइयां कार्य कर रही थीं, हालांकि, वे एसपीवी से जुड़े नहीं थे और सीएफसी का उपयोग करने में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वर्गीकृत फ्लाई ऐश, ईट निर्माण के लिए उपयोगी और किफायती नहीं है।
- प्रस्तावित इकाइयों को भूखंड आवंटन में विलंब हुआ और जिस क्षेत्र में भूखंड आवंटित किए जाने थे वहां सड़क, जल निकासी, विद्युतीकरण आदि बुनियादी ढांचे का अभाव था।
- वर्गीकृत फ्लाई ऐश के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए सीएफसी में एक बल्कर<sup>17</sup> खरीदा गया था, और इसे खाली करने/रिक्त करने के लिए एक विशेष प्रणाली की आवश्यकता थी। हालांकि, आवश्यक विशेष प्रणाली, व्यक्तिगत इकाइयों के पास उपलब्ध नहीं थी, और इसलिए, बल्कर का उपयोग नहीं किया गया।
- सीएफसी में परीक्षण प्रयोगशाला को न तो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त थी और न ही परीक्षण और प्रमाणन के लिए कोई योग्य कर्मचारी नियुक्त था। इस प्रकार, उन एजेंसियों को कोई वैध परीक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता था जिन्हें इकाइयां अपने उत्पादों की आपूर्ति करेंगी।
- सीएफसी में स्थापित प्रशिक्षण सुविधा का उपयोग नहीं हो रहा था।
- एसपीवी सदस्यों और मौजूदा फ्लाई ऐश ईट निर्माताओं के बीच खुला विरोधाभास और मतभेद था।

भारत सरकार द्वारा आगामी अनुदान जारी न किए जाने और इसके परिणामस्वरूप निधि की कमी के परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं ने सीएफसी के लिए शेष सामग्री और बैक-अप सेवाओं की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। यह भी देखा गया था कि फरवरी 2021

<sup>17</sup> बल्कर एक विशेष उद्देश्य वाहन है जो विशेष रूप से शुष्क फ्लाई ऐश के संग्रह, परिवहन और डी-कलेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। चेंसिस सहित बल्कर की लागत ₹77.04 लाख थी।

तक 42 इकाइयों में से 16 ने भूखंडों पर कब्जा ले लिया था जिनमें से केवल पांच इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया था। इसके अलावा, 50 अतिरिक्त इकाइयों/स्टार्टअप में से किसी ने भी क्लस्टर में अपनी इकाइयां स्थापित नहीं की थीं, जैसा कि परिकल्पित था। इसी प्रकार, क्लस्टर उत्पादन कारोबार में ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹70 करोड़ की वृद्धि करने और अतिरिक्त रोजगार सृजन का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

इसलिए, इससे न केवल योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका बल्कि सीएफसी की स्थापना पर ₹5.67 करोड़ के भारत सरकार के अनुदान सहित ₹8.89 करोड़ का निष्फल व्यय भी हुआ।

लेखापरीक्षा पैरा में उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार करते हुए एमएसएमई मंत्रालय के विकास कमिश्नर कार्यालय ने कहा (मार्च 2021 और जुलाई 2021) कि उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार को सीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के बारे में मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था (मार्च 2019) और सीएफसी के परिचालन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, अप्रैल 2019 और जून 2019 में अनुवर्ती अनुस्मारकों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मंत्रालय ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर कार्यान्वयन एजेंसी (एमआईडीसी) से शास्ति ब्याज के साथ-साथ अब तक जारी किए गए भारत सरकार के अनुदान की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस प्रकार, परियोजना की अनुपयुक्त योजना और निष्पादन, और एसपीवी सदस्यों को भूखंडों के आवंटन में देरी के कारण सीएफसी के पूरा होने और संचालन में विफलता, बुनियादी ढांचे के विकास की कमी और भारत सरकार से शेष अनुदान प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया बल्कि सीएफसी की स्थापना पर भारत सरकार की ₹5.67 करोड़ की अनुदान राशि सहित ₹8.89 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।